Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

19 जून 2025

NATIONAL AFFAIRS / GOVERNMENT SCHEME

1. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में IBCA की पहली बैठक की अध्यक्षता की।

16 जून 2025 को नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) की पहली बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक ने सात प्रमुख बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।

- **अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया, IBCA भारत के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से गठित एक गठबंधन है। इसमें बाघों, शेरों, तेंदुओं, हिम तेंदुओं, चीतों, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए समर्पित लगभग 95-97 सदस्य देश शामिल हैं।**

- **नौ बिग कैट क्षेत्र वाले देशों - भूटान, कंबोडिया, एस्वातिनी, गिनी, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया, कजाकिस्तान और भारत - के प्रतिनिधियों ने आधारभूत समझौतों का समर्थन करने और संयुक्त संरक्षण रणनीतियों के लिए प्रतिबद्धता जताने के लिए इस सम्मेलन में भाग लिया।**

- **सभा ने सर्वसम्मति से भूपेन्द्र यादव को IBCA का अध्यक्ष चुना तथा डॉ. एस.पी. यादव को महानिदेशक के रूप में अनुमोदित किया गया, जिससे संगठन का नेतृत्व ढांचा स्थापित हुआ।**

Key Points:-

(i) (i) प्रतिभागियों ने आईबीसीए-भारत मुख्यालय समझौते की पुष्टि की, प्रक्रिया के आंतरिक नियमों को अपनाया, वित्तीय प्रोटोकॉल और स्टाफ मैनुअल को मंजूरी दी, और संचालन समिति के परिणामों की पुष्टि की।

(ii) मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्यजीव संरक्षण में भारत की शानदार प्रगति पर प्रकाश डाला - जैसे कि दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों की रक्षा करना और चीतों को फिर से लाना। उन्होंने सदस्य देशों से अवैध शिकार से निपटने, आवासों की सुरक्षा करने और जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर पारिस्थितिकी तंत्र की लचीलापन बढ़ाने के लिए सामूहिक संरक्षण दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया।

(iii) पांच वर्षों (2023-24 से 2027-28) के लिए आवंटित ₹150 करोड़ के बीज अनुदान के साथ, IBCA का लक्ष्य तकनीकी क्षमता का निर्माण करना, संरक्षण की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और वैश्विक संसाधनों को जुटाना है। प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों में अवैध शिकार विरोधी उपाय, आवास बहाली और समुदाय द्वारा संचालित वन्यजीव संरक्षण पहल शामिल हैं।

2. अनंथा चंद्रकसन को MIT का पहला भारतीय मूल का प्रोवोस्ट नियुक्त किया गया, जो 1 जुलाई 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे।

18 जून, 2025 को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) ने घोषणा की कि डॉ. अनंथा पी. चंद्रकासन, जो मूल रूप से चेन्नई, भारत के निवासी हैं, को संस्थान का 14वां प्रोवोस्ट नियुक्त किया गया है। यह ऐतिहासिक नियुक्ति उन्हें MIT में इस शीर्ष शैक्षणिक पद को संभालने वाले पहले भारतीय-अमेरिकी बनाती है।

• चेन्नई में जन्मे और हाई स्कूल के दौरान अमेरिका चले गए चंद्रकासन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में BS (1989), MS (1990) और PhD(1994) की डिग्री हासिल की। 1994 में, वे MIT के संकाय में शामिल हो गए और नेतृत्व की भूमिकाओं के माध्यम से लगातार आगे बढ़े।

• उन्होंने माइक्रोसिस्टम्स टेक्नोलॉजी लैबोरेटरीज (2006-2011) के निदेशक के रूप में कार्य किया, EECS विभाग (2011-2017) का नेतृत्व किया और जुलाई 2017 में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के डीन बने। उन्होंने उद्यमशीलता, विविधता और छात्र-संकाय सहयोग का समर्थन करने वाले उल्लेखनीय कार्यक्रम पेश किए।

• 2024 में MIT के पहले मुख्य नवाचार और रणनीति अधिकारी नियुक्त किए गए, चंद्रकसन ने एमआईटी जलवायु और स्थिरता कंसोर्टियम, MIT-IBM वाटसन AI लैब, ह्यूमन इनसाइट कोलैबोरेटिव और जेनरेटिव AI इम्पैक्ट कंसोर्टियम जैसी विश्वविद्यालय-व्यापी पहलों का नेतृत्व किया।

Key Points:-

(i) डॉ. अनंथा चंद्रकासन को कम बिजली और ऊर्जा-कुशल सर्किट डिजाइन में उनके अग्रणी कार्य के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो आधुनिक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके नवाचारों ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बिजली की खपत को कम करने में मदद की है, जिससे स्मार्टफोन, पहनने योग्य उपकरण और एम्बेडेड सेंसर जैसी तकनीकें अधिक कुशल और टिकाऊ बन गई हैं। एमआईटी में, वह ऊर्जा-कुशल सर्किट और सिस्टम समूह का नेतृत्व करते हैं, जहां उनके शोध के परिणामस्वरूप कई प्रभावशाली पेटेंट और उच्च-प्रभाव वाले प्रकाशन हुए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर डिजाइन के भविष्य को आकार देना जारी रखते हैं।

(ii) चंद्रकसन ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार अर्जित किए हैं, जिनमें (इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स संस्थान) IEEE फेलो (2015), नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग और अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज दोनों के सदस्य, और IEEE, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन से पुरस्कार और कई मानद डॉक्टरेट शामिल हैं।

(iii) 1 जुलाई 2025 से प्रोवोस्ट के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हुए — जो कि MIT (मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) का मुख्य शैक्षणिक और वित्तीय पद होता है — वे फैकल्टी मामलों, शैक्षणिक योजना और बजट रणनीति की निगरानी करेंगे। MIT की अध्यक्ष सैली कोर्नब्लुथ ने उनके "चुस्त, उद्यमशील दृष्टिकोण" की सराहना की और उन्हें वित्तीय एवं वैश्विक अनुसंधान चुनौतियों से संस्थान को मार्गदर्शन देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला बताया।

3. GSEC लॉन्च के साथ हैदराबाद गूगल का साइबर सुरक्षा केंद्र बन गया।

17-18 जून 2025 को, गूगल ने हैदराबाद, तेलंगाना में अपने पहले गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र (GSEC) का उद्घाटन किया, जो एशिया-प्रशांत (APAC) क्षेत्र में अपनी पहली और विश्व स्तर पर चौथी सुविधा होगी, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री और IT मंत्री उपस्थित थे।

• GSEC का उद्घाटन 18 जून 2025 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी और IT एवं उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने किया। गूगल की कंट्री मैनेजर प्रीति लोबाना और वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे भारत के डिजिटल सुरक्षा ब्लूप्रिंट में एक मील का पत्थर बताया, जिसका उद्देश्य AI और साइबर सुरक्षा में उपयोगकर्ता के भरोसे को मजबूत करना है।

• यह केंद्र APAC में Google का पहला और दुनिया भर में चौथा केंद्र है, जो म्यूनिख, डबलिन और मलागा में सुविधाओं के साथ जुड़ता है। यह Google for India 2024 में की गई घोषणा पर आधारित है, जो वैश्विक तकनीकी निवेशों के लिए हैदराबाद के आकर्षण को मजबूत करता है।

• GSEC India ऑनलाइन धोखाधड़ी, मैलवेयर, एंटरप्राइज़ सुरक्षा और ज़िम्मेदार AI परिनियोजन को संबोधित करके Google के सुरक्षा चार्टर को कार्रवाई में बदल देगा। यह भारत के तेज़ी से विकसित हो रहे ऑनलाइन पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप गोपनीयता इंजीनियरिंग, सुरक्षा बुनियादी ढांचे और उन्नत डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करता है।

Key Points:-

(i) एंड्रॉइड पर वास्तविक समय घोटाले अलर्ट के लिए जेमिनी नैनो जैसे AI-संचालित तकनीक का उपयोग करना, गलत सूचना का पता लगाने के लिए सिंथआईडी वॉटरमार्किंग, गूगल पे सुरक्षा में सुधार और रेड-टीमिंग, केंद्र का उद्देश्य AI-संचालित खतरों के खिलाफ सक्रिय रक्षा तंत्र को मजबूत करना है।

(ii) हैदराबाद में पहले से ही Google के 7,000 कर्मचारियों के साथ, GSEC से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हज़ारों नौकरियाँ पैदा होने की उम्मीद है। यह शिक्षाविदों (जैसे IIT-मद्रास), स्टार्टअप और T-Fiber जैसे राज्य कार्यक्रमों के साथ सहयोग को बढ़ावा देगा, जिससे तेलंगाना को 2047 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 10% योगदान देने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

(iii) लॉन्च के दौरान, गूगल और तेलंगाना ने भविष्य की परियोजनाओं पर चर्चा की - क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, AI-आधारित ट्रैफ़िक प्रबंधन प्रणाली, बुद्धिमान शहरों का डिज़ाइन, गूगल स्टार्टअप हब और साइबर सुरक्षा कौशल पहल - जो निजी क्षेत्र और सरकार के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग का संकेत देते हैं।

4. महाराष्ट्र ने NEP 2020 के तहत प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी को वैकल्पिक तीसरी भाषा घोषित किया।

18 जून 2025 को, महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी को अनिवार्य के बजाय वैकल्पिक तीसरी भाषा बनाकर अपनी स्कूल भाषा नीति में बदलाव किया।

• महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने हाल ही में एक नया सरकारी संकल्प (GR) जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के छात्र अब किसी भी भारतीय भाषा को अपनी तीसरी भाषा के रूप में चुन सकते हैं। हिंदी अब अनिवार्य नहीं होगी, बल्कि एक वैकल्पिक या 'सामान्य' विषय होगी। यह नया नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में सुझाए गए त्रि-भाषा फॉर्मूले का अनुसरण करता है।

• इससे पहले अप्रैल 2025 में सरकार ने घोषणा की थी कि कक्षा 1 से हिंदी अनिवार्य होगी, जिसकी विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समूहों ने कड़ी आलोचना की थी। कई लोगों ने कहा कि इस फैसले में क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व को नजरअंदाज किया गया है और यह गैर-हिंदी भाषी छात्रों के साथ अन्याय है।

• शिवसेना (UBT), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और कई मराठी भाषा समूहों जैसे राजनीतिक दलों ने अप्रैल के फैसले का विरोध किया। उनका तर्क था कि इस कदम से मराठी भाषा की भूमिका कमजोर हो सकती है, जो राज्य की मातृभाषा है। इस दबाव के बाद सरकार ने फैसला वापस ले लिया।

Key Points:-

(i) राज्य सरकार ने बताया कि अपडेट किया गया GR पूरी तरह से NEP 2020 के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि छात्रों को तीन भाषाएँ पढ़नी होंगी- एक क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी और अपनी पसंद की एक और भारतीय भाषा। महाराष्ट्र में मराठी अनिवार्य बनी हुई है और तीसरी भाषा हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु या कोई अन्य भारतीय भाषा हो सकती है।

(ii) इस बदलाव ने स्कूलों और शिक्षा विभागों के लिए कुछ चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। बहु-भाषा विकल्पों के लिए पाठ्यपुस्तकें और अध्ययन सामग्री छापने की ज़रूरत है, और पाठ्यक्रम योजना को संशोधित करना होगा। बालभारती और एससीईआरटी (राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) जैसे संस्थान अब इस बदलाव को सुचारू रूप से लागू करने के लिए काम कर रहे हैं।

(iii) यह निर्णय दिखाता है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों को स्थानीय भाषा की पहचान के साथ कैसे संतुलित करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र ने अब अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है जो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं और सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करते हुए NEP 2020 का पालन करना चाहते हैं।

5. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्र को अगस्त 2025 से पश्चिम बंगाल में MGNREGA योजना फिर से शुरू करने का निर्देश दिया।

18 जून 2025 को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में 1 अगस्त 2025 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया, जिससे कथित अनियमितताओं के कारण लगभग तीन साल का निलंबन समाप्त हो गया।

• मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति चैताली चटर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि मनरेगा को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करना इसके विधायी उद्देश्य का उल्लंघन है; अदालत ने केंद्र को धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा उपाय करने की

अनुमति दी, लेकिन 1 अगस्त से पूरे राज्य में योजना को फिर से लागू करने का आदेश दिया।

• हुगली, पूर्वी बर्धमान, मालदा और दार्जिलिंग सहित कई जिलों में कथित बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के बाद मार्च 2022 में मनरेगा के वित्तपोषण पर रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया और ग्रामीण आजीविका का नुकसान हुआ।

• उच्च न्यायालय ने केंद्र को विशेष शर्तों के साथ संवितरण पुनः शुरू करने की अनुमति दी - जैसे कि जांच लंबित रहने तक जिला स्तर पर बहिष्करण, पारदर्शी प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण और नियमित ऑडिट - साथ ही यह भी कहा कि पिछले गड़बड़ी वाले खातों की जांच की जाएगी, लेकिन वर्तमान श्रमिकों को नुकसान नहीं होना चाहिए।

Key Points:-

(i) जबकि यह योजना पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्तपोषित है, HC ने जोर देकर कहा कि लंबित आरोपों के आधार पर आवंटन रोकना - जबकि 2022 से कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी - असंगत था। केंद्र को 15 अगस्त के बाद अगली सुनवाई से पहले अपने निर्णय और फंड वसूली की स्थिति को स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करना चाहिए।

(ii) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फ़ैसले का स्वागत किया, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य द्वारा लगभग 30 लाख मनरेगा मज़दूरों को ₹2,700 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जिससे वैकल्पिक योजनाओं के ज़रिए 1.5 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए हैं। उन्होंने तेज़ी से बहाली का आग्रह किया और ग्रामीण विकास निधि को रोकने के लिए केंद्र की आलोचना की।

(iii) यह योजना ग्रामीण परिवारों को सालाना 100 दिन का गारंटीकृत काम मुहैया कराती है, जो मजदूरी सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है। इसके फिर से शुरू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आने, संकट के चलते पलायन पर अंकुश लगने और पश्चिम बंगाल के लाखों श्रमिकों के लिए वित्तीय स्थिरता बहाल होने की उम्मीद है।

6. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम सम्मेलन में आईसीआर-ईआर, एनडीईएम लाइट 2.0 और बाढ़ खतरा क्षेत्रीकरण एटलस लॉन्च किया।

16 जून 2025 को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में आपदा प्रबंधन से संबंधित तीन अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन राहत आयुक्तों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों (SDRF) के वार्षिक सम्मेलन के दौरान किया गया। लॉन्च की गई तीन प्रमुख पहलें हैं — आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष (ICR-ER), आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस लाइट संस्करण (NDEM Lite 2.0), और असम का बाढ़ खतरा क्षेत्र निर्धारण एटलस (Flood Hazard Zonation Atlas)। इन सभी का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में प्रतिक्रिया की गति, समन्वय और सटीकता को बेहतर बनाना है।

• NDEM लाइट 2.0 मौजूदा जियो-पोर्टल को मोबाइल-फ्रेंडली इंटरफेस के साथ उन्नत करता है, जिससे NDRF, SDRF और जिला स्तर के कर्मियों को महत्वपूर्ण GIS मानचित्रों, वास्तविक समय के खतरे की चेतावनियों और एकीकृत परिचालन डेटा तक पहुंच मिलती है - यहां तक कि दूरस्थ स्थानों में भी - ताकि वे आपदाओं के दौरान एकजुटता और तेजी से कार्य कर सकें।

• बाढ़ खतरा क्षेत्रीकरण एटलस - असम का बाढ़ खाका: उपग्रह डेटा (1998-2023) और लगभग वास्तविक समय बाढ़-मानचित्रण का उपयोग करते हुए, एटलस बाढ़-प्रवण क्षेत्रों को गांव स्तर तक पहचानता है, जो असम के 28.5% जिलों को कवर करता है। यह नदी के जल स्तर, जलमग्न क्षेत्रों और सटीक जोखिम मानचित्रों में तत्काल दृश्यता प्रदान करता है - बाढ़ शमन, कृषि योजना और राहत कार्यों के लिए डेटा के साथ अधिकारियों को सशक्त बनाता है।

• राष्ट्रीय "शून्य-दुर्घटना" आपदा विजन: अमित शाह ने प्रतिक्रियात्मक राहत से सक्रिय, शून्य-दुर्घटना आपदा रणनीति में बदलाव पर जोर दिया, पिछले एक दशक में भारत की आपदा तत्परता को बढ़ाने के लिए NDMA, NDRF और CDRI जैसी संस्थाओं को श्रेय दिया। उन्होंने मजबूत जिला-स्तरीय बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए 90 दिनों के भीतर प्रत्येक जिला राहत आयुक्त को जिला आपदा प्रबंधन योजना विकसित करने में सक्षम बनाने पर जोर दिया।

Key Points:-

(i) गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ICR-ER प्लेटफ़ॉर्म, ISRO से लाइव सैटेलाइट इमेजरी को एकीकृत करता है, ताकि पूरे भारत में वास्तविक समय की स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके। यह केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच तुरंत डेटा साझा करने में सक्षम बनाता है - जिससे आपात स्थितियों के दौरान समन्वय और सूचित निर्णय लेने में तेज़ी आती है।

(ii) AI एनालिटिक्स, ड्रोन सर्विलांस, IoT सेंसर और सैटेलाइट संचार जैसे उपकरण अब सरकारी आपदा रणनीति के केंद्र में हैं। अमित शाह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये तकनीकें, प्लेटफ़ॉर्म समन्वय के साथ मिलकर बचाव कार्यों को तेज़, सुरक्षित और अधिक कुशल बना रही हैं - जिससे तहसील स्तर तक तैयारी का विस्तार हो रहा है।

(iii) असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बाढ़ के मैदानों के विकास को नियंत्रित करने, बाढ़-रोधी कृषि को बढ़ावा देने और फसल बीमा योजनाओं को दिशा देने में सहायता के लिए बाढ़ एटलस की प्रशंसा की। उन्होंने सामुदायिक शिक्षा, निकासी मानचित्रण और सटीक वैज्ञानिक इनपुट के आधार पर आपदा प्रतिक्रिया योजनाओं को संशोधित करने में इसके महत्व पर ध्यान दिलाया।

7. ECI ने 15 दिनों के भीतर EPICs वितरित करने के लिए नई SOP शुरू की।

18 जून 2025 को, भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) शुरू की, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPICs) किसी भी नए पंजीकरण या मतदाता सूची अपडेट के 15 दिनों के भीतर मतदाताओं तक पहुंच जाए। यह मतदाता-केंद्रित सेवाओं में एक बड़ा उन्नयन है।

• नए SOP के तहत, नए पंजीकृत मतदाताओं और अपने विवरण को अपडेट करने वाले दोनों को 15 दिनों के भीतर अपना EPIC प्राप्त होगा, जिससे पहले एक महीने से अधिक की प्रतीक्षा अवधि में काफी कमी आएगी।

• प्रत्येक चरण - निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा फॉर्म तैयार करने से लेकर भारतीय डाक द्वारा अंतिम वितरण तक - की वास्तविक समय में निगरानी की जाती है, तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को प्रत्येक चरण पर समय पर एसएमएस अलर्ट प्राप्त होता है।

• ECI ने अपने उन्नत ECINet प्लेटफ़ॉर्म के भीतर एक विशेष IT मॉड्यूल लॉन्च किया है, जो अब डाक विभाग (DoP) के

एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) के साथ सहज रूप से एकीकृत है। यह एकीकरण स्वचालित वर्कफ़्लो के माध्यम से संपूर्ण EPIC वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, वास्तविक समय ट्रैकिंग क्षमताओं को बढ़ाता है, और मतदाता कार्ड जारी करने के सभी चरणों में अधिक डेटा सुरक्षा, सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करता है।

Key Points:-

(i) नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) चुनाव आयोग के ECINet प्लेटफॉर्म और इंडिया पोस्ट प्रणाली के बीच एकीकृत समन्वय को मजबूत करती है। इसके तहत एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) के माध्यम से वास्तविक समय में डिलीवरी की जानकारी साझा की जाती है, जिससे EPIC (मतदाता फोटो पहचान पत्र) की ट्रैकिंग और वितरण के लिए एक सहज और प्रभावी राष्ट्रीय नेटवर्क सुनिश्चित होता है।

(ii) यह फास्ट-ट्रैक प्रणाली मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के "नागरिक-प्रथम" चुनावी सेवाओं के लिए जोर को दर्शाती है। इसका उद्देश्य मतदाता संतुष्टि को बढ़ावा देना, प्रशासनिक देरी को कम करना और जवाबदेह चुनावी शासन को बढ़ावा देना है।

(iii) यह SOP पहले के ECI सुधारों जैसे डुप्लिकेट EPIC नंबर और बेहतर EM सत्यापन प्रक्रियाओं को संबोधित करने का अनुसरण करता है। इनके साथ ही, 15-दिन की डिलीवरी का वादा चुनावी पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने और डिजिटल बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

INTERNATIONAL

1. UNGA ने 4 दिसंबर को एकतरफा दबावपूर्ण उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया और UNCITRAL (2025-2031) के लिए 34 सदस्यों का चुनाव किया।

16-18 जून 2025 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को एकतरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया और 2025-31 के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL) के लिए 34 सदस्य राज्यों को चुना।

- **16 जून 2025 को, UNGA ने 4 दिसंबर को एकतरफा जबरदस्ती उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके पक्ष में 116 वोट, विपक्ष में 51 वोट और 6 मत अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव में संप्रभु राष्ट्रों के खिलाफ़ दबाव के तौर पर संयुक्त राष्ट्र के आदेशों के बाहर प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव का इस्तेमाल करने की निंदा की गई है।**

- **यद्यपि बहुमत समर्थन विकासशील और वैश्विक दक्षिण देशों से आया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ के सदस्यों, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र ढांचे के भीतर राजनीतिकरण और संसाधनों के विचलन के बारे में चिंता जताते हुए इसका विरोध किया।**

- **नया दिवस इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे एकतरफा बलपूर्वक उपाय - जैसे प्रतिबंध, टैरिफ या बैंकिंग प्रतिबंध - मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, आर्थिक विकास को बाधित कर सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन को कमजोर कर सकते हैं। चीन, बेलारूस और अन्य देशों ने बहुपक्षीय शासन और**

निष्पक्षता का समर्थन करने में अपनी भूमिका पर जोर दिया।

Key Points:-

(i) उसी UNGA सत्र के दौरान, 34 सदस्य देशों को छह साल के कार्यकाल (2025-2031) के लिए UNCITRAL के लिए चुना गया। इनमें अफ्रीकी, एशियाई-प्रशांत, पूर्वी यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी देशों का मिश्रण शामिल है। यह आयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के लिए सामंजस्यपूर्ण रूपरेखा विकसित करता है।

(ii) उल्लेखनीय निर्वाचित UNCITRAL सदस्यों में जाम्बिया (अफ्रीका), श्रीलंका और वियतनाम (एशिया-प्रशांत), रूस (पूर्वी यूरोप), तथा मलेशिया, फिलीपींस, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य देश शामिल हैं - जो वैश्विक कानूनी सहयोग को मजबूत करते हैं।

(iii) यह दिवस मानवाधिकार और विकास के मुद्दे के रूप में एकतरफा आर्थिक दबाव के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के मानदंडों को मजबूत करता है। इस बीच, UNCITRAL के नवनिर्वाचित सदस्य व्यापार कानूनों, विवाद समाधान ढांचे और कानूनी सहायता के सामंजस्य को आगे बढ़ाएंगे, जिससे विशेष रूप से विकासशील और कम विकसित देशों को लाभ होगा।

BANKING & FINANCE

1. CCI ने 17 जून, 2025 को डेल्हीवरी द्वारा ईकॉम एक्सप्रेस के ₹1,407 करोड़ के अधिग्रहण और SML इसुजु में M&M की ₹555 करोड़ की हिस्सेदारी को मंजूरी दी।

17 जून 2025 को, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने दो प्रमुख अधिग्रहणों को मंजूरी दी: डेल्हीवरी द्वारा ईकॉम एक्सप्रेस का ₹1,407 करोड़ का अधिग्रहण और महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा SML इसुजु में ₹555 करोड़ की नियंत्रक हिस्सेदारी की खरीद।

• CCI ने ईकॉम एक्सप्रेस में 99.4% हिस्सेदारी के लिए डेल्हीवरी को ₹1,407 करोड़ में मंजूरी दे दी है। डेल्हीवरी के एमडी और सीईओ साहिल बरुआ ने कहा कि इस विलय से लागत दक्षता, डिलीवरी की गति और नेटवर्क पहुंच में सुधार होगा, जिससे भारत के ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में इसकी अग्रणी स्थिति मजबूत होगी।

• महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) को ₹555 करोड़ में SMLIsuzu का 58.96% हिस्सा खरीदने के लिए CCI की मंज़ूरी मिल गई है, जिसमें 26% अतिरिक्त शेयरों के लिए आगामी ओपन ऑफ़र भी शामिल है। इस लेन-देन का उद्देश्य भारी वाणिज्यिक वाहन खंड (3.5 टन से अधिक) में M&M की उपस्थिति को दोगुना करना है।

• CCI की मंजूरी के बाद, डेल्हीवरी के शेयर की कीमत बीएसई पर लगभग 1.6% बढ़कर ₹364.7 हो गई, जो लॉजिस्टिक्स समेकन के बारे में निवेशकों की आशावाद को दर्शाता है। विस्तारित बाजार हिस्सेदारी और तालमेल की उम्मीदों से प्रेरित होकर M&M के शेयरों में भी लगभग 3% की बढ़ोतरी हुई।

Key Points:-

(i) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत, CCI संभावित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रभाव के लिए विलय की समीक्षा करता है। दोनों सौदों को उपभोक्ता कल्याण या बाजार प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं पाया गया, जो नियामक के विकास-समर्थक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

(ii) ये स्वीकृतियाँ भारत के लॉजिस्टिक्स और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में चल रहे समेकन को दर्शाती हैं। डेल्हीवरी का लक्ष्य अपने लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और परिचालन दक्षता को मजबूत करना है, जबकि M&M SML Isuzu के साथ तालमेल के माध्यम से चीन और वैश्विक सीवी बाजारों में अपने प्रभुत्व को मजबूत करना चाहता है।

(iii) विलय के बाद, डेल्हीवरी का विस्तारित पदचिह्न स्वचालन और परिसंपत्ति उपयोग का समर्थन करता है, जबकि एमएंडएम ने वित्त वर्ष 31 तक 3.5 टन से अधिक सीवी में 10-12% बाजार हिस्सेदारी और वित्त वर्ष 36 तक 20% से अधिक का लक्ष्य रखा है। दोनों कंपनियाँ पैमाने और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए सीसीआई की मंजूरी को महत्वपूर्ण मानती हैं।

ECONOMY & BUSINESS

1. ICRA ने धीमी गति के बीच भारत की वित्त वर्ष 2026 की GDP वृद्धि 6.2% रहने का अनुमान लगाया है।

जून 2025 के मध्य में, क्रेडिट एजेंसी ICRA (निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) ने अनुमान लगाया कि भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि वित्त वर्ष 26 में 6.2% तक कम हो जाएगी, जो वित्त वर्ष 25 में अनुमानित 6.5% से मंदी को दर्शाता है, साथ ही मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि होने की उम्मीद है।

- **ICRA के नवीनतम पूर्वानुमान में वित्त वर्ष 26 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 6.2% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो वित्त वर्ष 25 में 6.5% से कम है, जबकि वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (GVA) वृद्धि 6.0% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 6.4% से कम है।**

- **एजेंसी मंदी के लिए आंशिक रूप से कमजोर व्यापारिक निर्यात और वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं को जिम्मेदार मानती है। हालांकि, सकारात्मक योगदानकर्ताओं में निरंतर ग्रामीण मांग, रबी की फसल की आय, कर राहत के माध्यम से राजकोषीय सहायता और मुद्रास्फीति से कम EMI भुगतान शामिल हैं।**

- **ICRA को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति 3.5% से अधिक होगी, जबकि थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति 1.8% से अधिक होगी। राजकोषीय घाटा GDP के 4.4% पर रहने का अनुमान है, जबकि चालू खाता घाटा (CAD) 1.2%-1.3% की सीमा में मध्यम है।**

Key Points:-

(i) केंद्र के पूंजीगत व्यय में लगभग 10% की वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे निवेश गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। फिर भी, निर्यात में कमजोरी और नीतिगत अनिश्चितता के बीच निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय धीमा बना हुआ है।

(ii) वित्त वर्ष 2025 में निर्माण, सेवाओं और ग्रामीण खपत के कारण 6.5% GDP वृद्धि हुई। लेकिन वैश्विक व्यापार और औद्योगिक मांग में नरमी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए संभावनाओं को कम कर दिया है।

(iii) जबकि ICRA ने 6.2% का अनुमान लगाया है, अन्य स्रोत थोड़े अलग अनुमान पेश करते हैं: नोमुरा को भी 6.2% की उम्मीद है, और आर्थिक सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष 26 के लिए

6.3-6.8% की सीमा का अनुमान लगाया है। इससे पहले मार्च में, ICRA 6.5% पर अधिक आशावादी था, हालांकि बाद में अपने रुख को नीचे की ओर संशोधित किया।

AWARDS

1. वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय को IGNCA समारोह में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

जून 2025 में, वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के अध्यक्ष - को पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता देते हुए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

• IGNCA में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने घोषणा की कि IGNCA के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में संस्थान के साथ राय के असाधारण जुड़ाव को दर्शाया गया और इसमें ट्रस्टी, विद्वान और साथी पुरस्कार विजेता शामिल हुए।

• 1946 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सोनारी में जन्मे राम बहादुर राय ने हिंदुस्तान समाचार से शुरुआत की और फिर जनसत्ता में ब्यूरो चीफ और न्यूज़ एडिटर बने। उन्होंने नवभारत टाइम्स के लिए विशेष संवाददाता के रूप में भी काम किया, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जैसी प्रमुख घटनाओं को फील्ड रिपोर्ट के साथ कवर किया।

• राम बहादुर राय ने प्रभावशाली जीवनियां लिखीं - जिनमें मंजिल से ज्यादा सफर (वीपी सिंह), शाश्वत विद्रोही राजनेता (आचार्य जेबी कृपलानी), रहवारी के सवाल (चंद्रशेखर) शामिल हैं - और संविधान और समाजवाद पर विद्वतापूर्ण रचनाएं शामिल हैं। एक छात्र नेता के रूप में, वह जेपी आंदोलन में शामिल हुए और आपातकाल के दौरान मीसा के तहत जेल जाने वाले पहले लोगों में से थे।

Key Points:-

(i) 2015 से राय IGNCA बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो कला, सांस्कृतिक विरासत और अंतःविषय संवाद को बढ़ावा देते हैं। वे SGT विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य करते हैं, भविष्य के नेताओं को शिक्षित करते हैं और राष्ट्रीय शैक्षिक सुधारों को संबोधित करने वाले अकादमिक सम्मेलनों का समर्थन करते हैं।

(ii) पद्म भूषण से पहले राम बहादुर राय को पत्रकारिता और साहित्य के लिए 2015 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने माधवराव सप्रे, माणिकचंद्र वाजपेयी, भगवानदास और सत्याग्रही सम्मान जैसे पत्रकारिता पुरस्कार भी जीते, जो इस क्षेत्र में उनके प्रभाव और दीर्घावधि की पुष्टि करते हैं।

(iii) भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा को मान्यता देता है। साहित्य और शिक्षा-पत्रकारिता में राय की मान्यता सार्वजनिक विमर्श को आकार देने, लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने और बौद्धिक विचार नेताओं को सलाह देने में उनकी भूमिका को रेखांकित करती है।

2. साहित्य अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं में 2025 बाल साहित्य पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की।

18 जून 2025 को, संस्कृति मंत्रालय के तहत भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी ने सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कार (बाल साहित्य पुरस्कार) के 24 प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की।

• साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में हुई कार्यकारी बोर्ड की बैठक में इन पुरस्कारों को मंजूरी दी गई। प्रत्येक भाषा के लिए तीन सदस्यीय निर्णायक मंडल ने जनवरी 2019 से दिसंबर 2023 के बीच प्रकाशित कृतियों का मूल्यांकन किया और अंततः 24 उत्कृष्ट कृतियों का चयन किया।

• पूर्वोत्तर के लेखकों को उल्लेखनीय सफलता मिली: असमिया में सुरेन्द्र मोहन दास को मैनाहातर पद्य (कविता) के लिए तथा बोडो में बिनय कुमार ब्रह्मा को खांथी ब्स्वन अरव अखु दानई (कहानी संग्रह) के लिए पुरस्कार मिला। मणिपुर के लेखकों को भी अतिरिक्त सम्मान मिला।

• गुजराती भाषा में कवि कीर्तिदा ब्रह्मभट्ट को उनकी बच्चों की कविता पुस्तक तिनचक के लिए सम्मानित किया गया, जो पहली बार 2022 में प्रकाशित हुई। अकादमी ने सरल लेकिन अभिव्यंजक छंदों के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों को व्यक्त करने की कृति की क्षमता की सराहना की।

Key Points:-

(i) बाल साहित्य पुरस्कार के साथ-साथ साहित्य अकादमी ने युवा लेखकों के लिए युवा पुरस्कार के 23 विजेताओं की भी घोषणा की। उल्लेखनीय प्राप्तकर्ताओं में अद्वैत कोटारी (अंग्रेजी) और पार्वती तिर्की (हिंदी) शामिल हैं, जिन्हें समान मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद चुना गया।

(ii) प्रत्येक बाल साहित्य पुरस्कार विजेता को एक उत्कीर्ण ताम्र पट्टिका और ₹50,000 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा, जिसका बाद में युवा पुरस्कार विजेताओं के साथ नई दिल्ली में औपचारिक वितरण किया जाएगा।

(iii) साहित्य अकादमी द्वारा 2010 में स्थापित बाल साहित्य पुरस्कार एक प्रतिष्ठित सम्मान बन गया है जो सभी 24 मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में बाल लेखकों को प्रोत्साहित करता है, भाषाई विविधता को बढ़ावा देता है और भारत की साहित्यिक विरासत को समृद्ध करता है।

SUMMITS & CONFERENCE / COMMITTEES & MEETINGS

1. भारत और यूक्रेन ने 2024 द्विपक्षीय समझौते के तहत कृषि सहयोग पर पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित की।

2024 के द्विपक्षीय समझौते के बाद, भारत और यूक्रेन ने अगले पांच वर्षों के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान, व्यापार और प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान की रूपरेखा तैयार करने के लिए जून 2025 में कृषि सहयोग पर अपना पहला संयुक्त कार्य समूह (JWG) बुलाया।

• अगस्त 2024 में कृषि और खाद्य उद्योग में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी और राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अनुमोदित किया, दोनों देशों ने एक संयुक्त कार्य समूह (JWG) का गठन किया। यह निकाय कृषि, अनुसंधान, व्यापार और खाद्य सुरक्षा में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए हर दो साल में एक बार बैठक करता है।

• JWG का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है: कानूनी मानकों का आदान-प्रदान, फसल आनुवंशिकी, पौध संरक्षण विधियाँ, सिंचाई तकनीकें (विशेष रूप से सूक्ष्म सिंचाई), उर्वरक उपयोग और बीज प्रमाणीकरण। यह जलीय कृषि, पशुधन सुधार, मशीनीकरण और कृषि-जैव प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान की सुविधा भी प्रदान करेगा।

• बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा की गई - जिसमें ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) के वैज्ञानिकों का समर्थन प्राप्त था - और यूक्रेन के कृषि नीति मंत्रालय, जिसका नेतृत्व कार्यवाहक मंत्री तरास वायसोत्स्की ने किया, ने उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

Key Points:-

(i) संयुक्त कार्य समूह का मुख्य उद्देश्य मानकों, पैकेजिंग और खाद्य सुरक्षा मानदंडों पर जानकारी का आदान-प्रदान करके और संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देकर "अनुकूल बाजार स्थितियां" बनाना है। इसका लक्ष्य द्विपक्षीय कृषि व्यापार का विस्तार करना और प्रत्येक देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है।

(ii) संयुक्त कार्य समूह ने जीनोमिक्स, पादप प्रजनन, जैव प्रौद्योगिकी, जलीय कृषि और मत्स्य प्रौद्योगिकी, मृदा उत्पादकता, जल प्रबंधन और आधुनिक कृषि मशीनीकरण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त वैज्ञानिक प्रयासों के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार की है। इन पहलों को संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा और बाद में इनका विस्तार किया जाएगा।

(iii) वर्तमान संयुक्त कार्य समूह की बैठक पांच वर्षों के लिए वैध समझौते के तहत होती है, जिसे पांच-वर्षीय वेतन वृद्धि में स्वचालित रूप से बढ़ाया जा सकता है। भारत और यूक्रेन के बीच हर दो साल में बैठकें बारी-बारी से होंगी। आगामी कार्यों में कार्य योजनाओं का मसौदा तैयार करना, अनुसंधान प्राथमिकताएँ निर्धारित करना और सूक्ष्म सिंचाई, डेयरी प्रजनन और बीज प्रमाणीकरण में पायलट परियोजनाओं की पहचान करना शामिल है।

IMPORTANT DAYS

1. अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 2025 – 18 जून।

हर साल 18 जून को, दुनिया भर में पिकनिक के शौकीन लोग अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाते हैं, यह दिन बाहर भोजन करने के सरल आनंद का सम्मान करता है - यह परंपरा 18वीं शताब्दी के फ्रांस से शुरू हुई थी।

• पिकनिक - फ्रेंच पिके-निक से - फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकप्रिय हो गया जब शाही पार्क जनता के लिए खोले गए। 19वीं सदी तक, यह एक आरामदेह सामाजिक आयोजन के रूप में विकसित हो गया था। पिकनिक बाद में शांतिपूर्ण सभाओं और यहां तक कि छोटे विरोध स्थलों के रूप में भी काम करने लगे, जैसे कि 1989 में ऑस्ट्रिया-हंगरी के पास पैन-यूरोपियन पिकनिक।

• हालाँकि यह एक अनौपचारिक वैश्विक उत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस हर साल 18 जून को मनाया जाता है, जिसे दुनिया भर के कैलेंडर में अंकित किया जाता है। 2025 में, यह बुधवार को पड़ता है, जो दिनचर्या से अलग हटकर सप्ताह के बीच में एक अवसर प्रदान करता है।

• उत्तरी गोलार्ध में जून का महीना गर्मियों के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जो इसे आउटडोर भोजन के लिए आदर्श बनाता है। दक्षिणी गोलार्ध के इलाकों में रहने वाले लोग घरों या सामुदायिक हॉल में इनडोर या आश्रय वाले "पिकनिक" का भी आनंद लेते हैं।

Key Points:-

(i) पनीर, फल, ब्रेड, सलाद और ताज़ा पेय की टोकरी पैक करके जश्न मनाएँ। पार्क में, झील के किनारे या स्कूल के लॉन में कंबल बिछाएँ। फ्रिसबी या बैडमिंटन जैसे हल्के खेल शामिल करें और वंचित बच्चों के लिए सामूहिक भोजन, पॉटलक या धर्मार्थ पिकनिक में भाग लें।

(ii) आजकल की पिकनिक सरल लेकिन सार्थक होती है- कुछ लोग पड़ोस की बेंच पर आरामदेह भोजन के साथ तनाव कम करते हैं, जबकि अन्य लोग मौसमी व्यंजनों के साथ पिकनिक मनाते हैं। वे अनौपचारिक सामाजिक बंधन अनुष्ठानों और दैनिक व्यस्तता से थोड़ी राहत के रूप में काम करते हैं।

(iii) सबसे बड़े पिकनिक का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2009 में पुर्तगाल के लिस्बन में बनाया गया था, जिसमें 22,000 से ज़्यादा प्रतिभागी शामिल हुए थे। बॉलीवुड अभिनेता शरमन जोशी, जो अब टोरंटो में हैं, ने रिवरडेल में परिवार के साथ अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया, जहाँ उन्होंने पनीर, डार्क चॉकलेट और बाहर सूर्यास्त का आनंद लिया।

2. विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस 2025 – 18 जून।

प्रत्येक वर्ष 18 जून को मनाया जाने वाला विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस, ऑटिस्टिक व्यक्तियों की शक्तियों, पहचान और अधिकारों का सम्मान करता है, तथा वैश्विक न्यूरोडायवर्सिटी आंदोलन के साथ तालमेल बिठाते हुए कहानी को कमी से भिन्नता की ओर ले जाता है।

• एस्पीज़ फ़ॉर फ़्रीडम द्वारा 2005 में शुरू की गई यह तिथि समूह के सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्मदिन को चिह्नित करती है और LGBTQ+ प्राइड आंदोलन का मॉडल है। ऑटिस्टिक लोगों के नेतृत्व में होने वाला यह कार्यक्रम दया नहीं बल्कि गर्व का एहसास कराता है, इस बात पर ज़ोर देता है कि ऑटिज़्म एक प्राकृतिक बदलाव है, कोई बीमारी नहीं।

• 2025 की थीम "अनएपोलोजेटिकली ऑटिस्टिक" आत्म-स्वीकृति और चुनौतियों को छिपाने का आह्वान करती है - मानदंडों को फिट करने के लिए ऑटिस्टिक लक्षणों को छिपाने का अभ्यास। यह ऑटिस्टिक व्यक्तियों को प्रामाणिक और गर्व से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है।

• विश्वव्यापी कार्यक्रमों में वर्चुअल मीटअप, कला प्रदर्शनियां, पैनल चर्चाएं, पिकनिक और सोशल मीडिया अभियान शामिल हैं, जिनमें इंद्रधनुष-अनंत प्रतीक शामिल है, जो अनंत तंत्रिका-विविधता का जश्न मनाता है और जिसका नेतृत्व ऑटिस्टिक आवाजों द्वारा किया जाता है।

Key Points:-

(i) यह दिन समावेशिता और अधिकारों पर प्रकाश डालता

है, इस बात पर जोर देता है कि ऑटिस्टिक व्यक्ति अपने बारे में कथाएं गढ़ें ("हमारे बिना हमारे बारे में कुछ भी नहीं")। यह समाज में शिक्षा, रोजगार और आवास तक बेहतर पहुंच का आह्वान करता है।

(ii) विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस अद्वितीय प्रतिभाओं पर प्रकाश डालता है - पैटर्न सोच और रचनात्मकता से लेकर सटीकता, फोकस और वैकल्पिक समस्या-समाधान विधियों तक। यह पुष्टि करता है कि ऑटिस्टिक ताकतें समाज को समृद्ध करती हैं, न कि केवल चुनौतियों की भरपाई करती हैं।

(iii) यह एक वार्षिक उत्सव से कहीं ज़्यादा है, यह दिन स्कूलों, कार्यस्थलों, स्वास्थ्य सेवा और मीडिया में बदलाव का बीजारोपण करता है। 2025 की थीम के अनुसार, समुदायों से साल भर स्वीकृति की अपील की जाती है, जिससे ऑटिस्टिक लोगों को सार्वजनिक जीवन के सभी पहलुओं में बेबाकी से जीने का मौक़ा मिल सके।

DEFENCE

1. पहला भारत-अमेरिका विशेष बल अभ्यास "टाइगरक्लॉ 2025" उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ।

26 मई से 10 जून 2025 तक, भारतीय वायुसेना के विशिष्ट गरुड़ कमांडो और यूएसएएफ के विशेष रणनीति स्क्वाड्रन ने टाइगर क्लॉ 2025 का आयोजन किया - भारत और अमेरिका का पहला स्वतंत्र द्विपक्षीय वायु सेना विशेष बल अभ्यास, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश के चांदीनगर में गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र में किया गया और उत्तर भारत के ऊंचाई वाले और शहरी क्षेत्रों में आयोजित किया गया।

• पिछले बहु-डोमेन अभ्यासों से एक ऐतिहासिक बदलाव में, टाइगरक्लॉ ने विशेष रूप से विशेष बलों की अंतर-संचालनीयता पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें हवाई और हेलीबॉर्न प्रविष्टियां (स्थिर-रेखा और मुक्त-पतन), CQB और बंधक बचाव, JTAC एकीकरण के साथ एयरफील्ड जब्ती, रात के समय उच्च मूल्य लक्ष्य अभ्यास, युद्ध हताहत देखभाल और ISR-ड्रोन समन्वय शामिल थे।

• दो सप्ताह तक गहन अभ्यास के दौरान कमांडो ने पंजाब और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों से लेकर हिमाचल प्रदेश की दुर्गम चोटियों तक की यात्रा की तथा वास्तविक दुनिया की आकस्मिक परिस्थितियों का अनुकरण किया।

• अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सिद्धांतों और रणनीतियों का परस्पर आदान-प्रदान था: युद्ध-प्रशिक्षण, कार्रवाई के बाद की समीक्षा और लाइव संचार अभ्यास ने युद्ध के मैदान में तालमेल को और बेहतर बनाया। USAF ने गरुड़ की इलाके की सूझबूझ और लचीलेपन की प्रशंसा की, जबकि भारतीय सेनाओं ने अपने अमेरिकी समकक्षों के सटीक हमले और तकनीक-प्रेमी तरीकों की सराहना की।

Key Points:-

(i) प्रशिक्षण रणनीति से परे, टाइगरक्लॉ ने रणनीतिक महत्व हासिल किया, जिसने दक्षिण एशिया के बदलते भू-राजनीतिक माहौल के बीच भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को मजबूत किया। जबकि अमेरिका पाकिस्तान को सुरक्षा सहायता जारी रखता है, यह अभ्यास भारत में उसके बढ़ते रणनीतिक विश्वास और एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

(ii) संस्थागत गति अब टाइगरक्लॉ को एक वार्षिक, रोटेशनल इवेंट बनाने के पक्ष में है, जिसमें संभावित रूप से भारतीय सेना के पैरा-SF, नौसेना के मार्कोस और यूएस एसओसीओएम इकाइयां शामिल हो सकती हैं। यह आगरा में स्थित भारत के उभरते सशस्त्र बल विशेष संचालन प्रभाग (AFSOD) के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, और भारत-

अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI) के साथ मिलकर काम करता है - साझा संचार तकनीक, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के लिए रास्ते खोलता है।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. एयरटेल और जियो के स्पेसएक्स के साथ जुड़ने से स्टारलिंक को भारत में आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त हुआ।

जून 2025 के मध्य में, भारत के दूरसंचार विभाग ने स्टारलिंक (स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा) को आधिकारिक लाइसेंस प्रदान किया, क्योंकि भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने इसे वितरित करने और समर्थन देने के लिए साझेदारी सौदों पर हस्ताक्षर किए।

• 17 जून 2025 को संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स के ज़रिए घोषणा की कि स्टारलिंक ने भारत में इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करने के लिए अपना लाइसेंस हासिल कर लिया है। उन्होंने इसे एक परिवर्तनकारी कदम बताया और सैटेलाइट कनेक्टिविटी को "अगला मोर्चा" और देश के डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए उत्प्रेरक बताया।

• भारत की 1.4 बिलियन आबादी के 40% से अधिक लोग विश्वसनीय ब्रॉडबैंड की कमी वाले क्षेत्रों में रहते हैं, स्टारलिंक की LEO-आधारित वास्तुकला - पृथ्वी से लगभग 550 किमी ऊपर उपग्रहों का उपयोग करते हुए - पहाड़ी और वन क्षेत्रों में भी उच्च गति (25-220 Mbps), कम विलंबता इंटरनेट का वादा करती है।

• मार्च 2025 में, एयरटेल और रिलायंस जियो ने स्टारलिंक को सह-मार्केट करने के लिए स्पेसएक्स के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इन साझेदारियों के तहत, दूरसंचार कंपनियाँ अपने मौजूदा खुदरा नेटवर्क के माध्यम से बिक्री, किट स्थापना, ग्राहक सहायता और थोक उद्यम वितरण को संभालेंगी।

Key Points:-

(i) स्टारलिंक के हार्डवेयर किट (डिश, मॉडेम, ट्राइपॉड) की कीमत लगभग ₹33,000 होने की उम्मीद है। मासिक अनलिमिटेड प्लान की कीमत ₹3,000 हो सकती है, जबकि संभावित कम लागत वाला प्रोमो प्लान ₹840 के करीब हो सकता है।

(ii) लाइसेंस अनुदान के बाद, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) द्वारा 15-20 दिनों के भीतर परीक्षण स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाने की उम्मीद है। सभी तकनीकी और सुरक्षा मंज़ूरी पूरी होने के बाद, 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में पूर्ण वाणिज्यिक सेवाएँ शुरू होने की उम्मीद है।

(iii) दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कम्पनियों एयरटेल और जियो ने सीओएआई के माध्यम से प्रस्तावित कम सैटेलाइट स्पेक्ट्रम शुल्क के बारे में चिंता जताई है - जो वर्तमान में वार्षिक राजस्व का लगभग 4% है - जिसके बारे में उनका तर्क है कि इससे स्थलीय ऑपरेटरों को नुकसान हो सकता है, जो नीलामी के माध्यम से 20% से अधिक का भुगतान करते हैं।

BOOKS & AUTHORS

1. ए.के. भट्टाचार्य की तीसरी पुस्तक भारत की आर्थिक यात्रा (1998-2014) का अन्वेषण करती है।

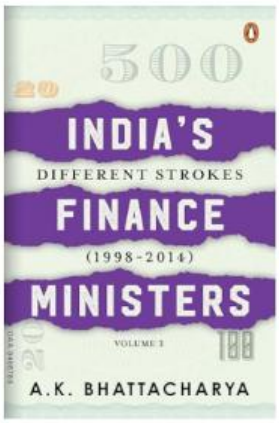

मार्च 2025 में प्रकाशित, ए.के. भट्टाचार्य की तीसरी पुस्तक जिसका शीर्षक है भारत के वित्त मंत्री: विभिन्न स्ट्रोक (1998-2014), चार वित्त मंत्रियों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण का पता लगाती है, जिसमें 1998 के बाद बजट, गठबंधन राजनीति और सुधार के मार्ग पर प्रकाश डाला गया है।

• यह तीसरी किस्त भट्टाचार्य के 2023 और 2024 संस्करणों का अनुसरण करती है, जिसमें 1947-1977 और 1977-1998 को शामिल किया गया है। यह दस्तावेज करता है कि कैसे 1998-2014 की अवधि में, गठबंधन सरकारों के तहत, चार वित्त मंत्रियों ने राजनीतिक कमज़ोरियों के बीच बजट का संचालन किया - यह पता लगाने के लिए कि कैसे प्रत्येक ने सुधार, स्थिरता और संकट प्रबंधन के माध्यम से भारत के मार्ग को आकार दिया।

• यह पुस्तक चार वित्त मंत्रियों: यशवंत सिन्हा, पी. चिदंबरम, प्रणब मुखर्जी और पी. चिदंबरम (दूसरा कार्यकाल) के बारे में गहन जानकारी प्रदान करती है। इसमें उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि, पेशेवर यात्रा, नीतिगत प्राथमिकताएँ और गठबंधन की बाधाओं, वैश्विक आर्थिक झटकों और घरेलू दबावों से निपटने के उनके तरीके का वर्णन किया गया है।

• किस्से-कहानियों और गहन शोध को मिलाकर, पुस्तक बजटीय निर्णयों और गठबंधन राजनीति के बीच नाजुक अंतर्संबंध को उजागर करती है। भट्टाचार्य दिखाते हैं कि मंत्रियों ने विनिवेश, राजकोषीय समेकन, बैंकिंग सुधार जैसे सुधार एजेंडों को गठबंधन नेताओं की मांगों और खंडित संसदीय जनादेश के साथ कैसे संतुलित किया।

Key Points:-

(i) यह पुस्तक 1998 से 2014 के बीच भारत में हुए प्रमुख आर्थिक घटनाक्रमों का विश्लेषण करती है, जिसमें एशियाई वित्तीय संकट, 2003 के कर सुधार, 2008 की वैश्विक मंदी और माल एवं सेवा कर (GST) के लिए प्रारंभिक आधार तैयार करना शामिल है। लेखक इन महत्वपूर्ण चरणों के दौरान नीतिगत प्रतिक्रियाओं और आर्थिक लचीलेपन का पता लगाता है।

(ii) विभिन्न वित्त मंत्रियों के कार्यकाल और बजट चक्रों के इर्द-गिर्द संरचित, प्रत्येक अध्याय में बैंक पुनर्पूंजीकरण, एफडीआई उदारीकरण और राजकोषीय नीति बदलाव जैसे प्रमुख सुधारों पर सारांश तालिकाएँ, तुलनात्मक डेटा और केस स्टडी शामिल हैं। यह पुस्तक आज की आर्थिक बहसों के लिए प्रासंगिक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है।

ENVIRONMENT

1. दक्षिण भारत में नई जंपिंग स्पाइडर प्रजाति स्पार्टेयस करिगिरी की खोज की गई।

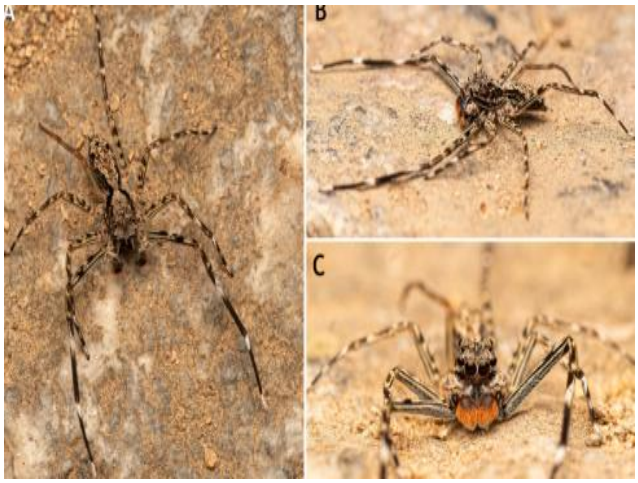

जून 2025 में, वैज्ञानिकों ने कर्नाटक और तमिलनाडु में साल्टिसिडे परिवार की एक नई जम्पिंग स्पाइडर प्रजाति, स्पार्टेयस करिगिरी की खोज की - जो भारत में स्पार्टेयस वंश का पहला रिकॉर्ड था।

• चेन्नई के शोधकर्ताओं ने स्पार्टेइनी उपपरिवार में स्पार्टेअस करिगिरी की पहचान की - यह भारत में पुष्टि की गई पहली स्पार्टेअस प्रजाति है, जो पहले केवल दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन के कुछ हिस्सों में ही ज्ञात थी।

• कर्नाटक के देवरायणदुर्ग में करिगिरी (हाथी पहाड़ी) के नाम पर इस प्रजाति का नाम रखा गया है, जिसे तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में भी पाया गया है, जिससे इसके ज्ञात निवास स्थान का विस्तार प्रकार स्थान से परे हो गया है।

• यह फुर्तीला शिकारी उन्नत दृष्टि और बुद्धिमान शिकार रणनीति का प्रदर्शन करता है - कीटों को पकड़ने के लिए वेब आक्रमण और शिकार की नकल का उपयोग करता है - जो कूदने वाली मकड़ियों (साल्टिसीडे) की विशेषता है।

Key Points:-

(i) चट्टानी इलाकों और जंगली इलाकों में पाए जाते हैं, दरारें और कूड़े जैसे सूक्ष्म आवासों में रहते हैं। नर होलोटाइप और मादा नमूनों को छायादार चट्टानी सतहों और ज़मीनी कूड़े से एकत्र किया गया था।

(ii) इसकी खोज के साथ ही भारत की ज्ञात देशी स्पार्टेइना जंपिंग मकड़ियों की संख्या 10 प्रजातियों में 15 हो गई है। इससे स्पार्टेयस और संबंधित जीनस सोनोइटा दोनों का भौगोलिक वितरण बढ़ गया है।

(iii) सहकर्मी-समीक्षित पत्रिकाओं में प्रलेखित, एस. करिगिरी ने दक्षिणी भारत में अरचिन्ड विविधता, जैव भूगोल और शिकारी अनुकूलन पर नई रोशनी डाली है। यह चट्टानी आवासों में आगे के पारिस्थितिक सर्वेक्षणों को भी प्रेरित करता है।

Static GK

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC)	केंद्रीय मंत्री: भूपेन्द्र यादव	मुख्यालय: नई दिल्ली
Uttar Pradesh	मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ	राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल
Google	CEO : सुंदर पिचाई	मुख्यालय: माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
Maharashtra	मुख्यमंत्री: देवेंद्र फडणवीस	राज्यपाल: सी. पी. राधाकृष्णन
Ukraine	प्रधान मंत्री: डेनिस श्म्यहाल	राजधानी: कीव
UNGA	अध्यक्ष: एनालेना बैरबॉक	मुख्यालय: न्यूयॉर्क
Assam	मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा	राज्यपाल: लक्ष्मण आचार्य
the Election Commission of India (ECI)	स्थापना : 1950	मुख्य चुनाव आयुक्त: ज्ञानेश कुमार
ICRA Limited	CEO : रामनाथ	मुख्यालय: भारत
	कृष्णन	
CCI	अध्यक्ष: रवनीत कौर	मुख्यालय: नई दिल्ली